****

Press Release

**COVID-19** तालाबंदी (लॉकडाउन) में नागरिक समाज नेतृत्व (सिविल सोसाइटी लीडर्स) की धारणाएं और अनुभव[[1]](#footnote-1)

नागरिक समाज संगठनों का रैपिड सर्वे (3 मई से 10 मई, 2020)

*संक्षिप्त विवरण:*

3 *मई से* 10 *मई 2020 के बीच किए गए लगभग* 70 *नागरिक समाज नेताओं के सर्वेक्षण सरकार और नागरिक समाज के बीच अधिक समन्वय की तत्काल आवश्यकता की ओर संकेत करता है।* COVID-19 *संकट का मुकाबला करने के लिए चल रहे काम के बारे में अपने अनुभवों और धारणाओं का अनुमान लगाने के लिए आयोजित किए गए इस सर्वेक्षण में अलग-अलग आकार के और विविध भौगोलिक क्षेत्रों में काम कर रहे संगठनों के नेताओं को शामिल किया गया है। परिणामों की प्रतिक्रिया में, प्रोफेसर मधुकर शुक्ला और एमएस श्रीराम - नागरिक समाज के दो श्रेष्ठ शोधकर्ता – ने नागरिक समाज के लिए इस अभूतपूर्व समय में रणनीतियों और कार्यपद्धतियों को फिर से बनाने के तरीकों पर ज़ोर दिया। इन निष्कर्षों के आधार पर हम लेन-देन-आधारित मॉडल (ट्रांज़ैक्शन-बेस्ड मॉडल) से हटकर विश्वास पर आधारित मॉडल (ट्रस्ट बेस्ड मॉडल) का प्रस्ताव रखना चाहेंगे, जो ज़मीनी कार्यकर्ताओं को अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्रदान करेगा।*

*पूरी रिपोर्ट निम्नलिखित साइट पर उपलब्ध है :*

<https://sites.google.com/iima.ac.in/rterc/research?authuser=0>

*सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष:*

* *समुदाय में लोग सरकारी सेवाओं और नीतियों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और एक बड़ा वर्ग कोरोनावायरस से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इससे परिचित नहीं हैं****: 40% से अधिक संगठनों ने पाया कि जिन समुदायों में वे काम कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश घर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और 20% से अधिक संगठनों ने पाया कि समुदायों को आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी नहीं है। यह प्रवृत्ति छोटे संगठनों में और भी अधिक है।***
* *संगठन उपयोगी रूप से सरकार के साथ साझेदारी करने में सक्षम नहीं हैं****: लगभग आधे नागरिक समाज नेताओं उन सरकारी अधिकारियों तक सुलभता से नहीं पहुँच पाए जिनकी उन्हें ज़मीन पर काम करने के लिए ज़रूरत है। दो-तिहाई से अधिक ने महसूस किया कि नीतियां बनाने वाले अफ़सर उनके सुझावों को लेकर बहुत ग्रहणशील नहीं थे। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और छोटे संगठनों के लिए सरकारी अधिकारियों तक पहुँचना और भी मुश्किल था।***

***केवल लगभग 10% संगठनों के जवाबों से पता चलता है कि वे सीधे सरकार के प्रयासों में शामिल थे और 40% से अधिक ने कहा कि उनके काम के लिए सरकार के साथ समन्वय करना सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल था।***

* *सरकारी सूचनाएँ और निर्देश भ्रामक हैं/ समझने में कठिन हैं:* ***लगभग आधे नागरिक समाज संगठनों को अपने काम के लिए सरकारी निर्देशों को समझने में कठिनाई हुई है। राहत प्रयासों के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने में सारा समय जा रहा है: सर्वेक्षण में पाया गया कि वित्तीय संसाधनों को जुटाना संगठनों के लिए सबसे अधिक समय लेने वाली गतिविधि है और करीब 60 % संगठनों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आवश्यक संसाधनों का एक बड़ा भाग स्वतन्त्र राहत प्रयासों के लिए (सरकार से किसी भी मदद के बिना) हो सकता है जिसमें आधे संगठनों ने अपना अधिकांश समय जाने की सूचना दी है।***
* *नागरिक समाज नेतृत्व को दाताओं (डोनर) द्वारा लम्बे समय से चल रहे अन्य प्रयासों की उपेक्षा की चिंता है :* ***कई नेताओं ने अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कुपोषण, शिक्षा, घरेलू हिंसा, बाल दुर्व्यवहार, और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों की उपेक्षा या उन्हें किनारे (सरकार और दाताओं द्वारा) करने के सन्दर्भ में अपनी चिंताओं को साझा किया। कई संगठनों ने व्यक्त किया कि ये कई सालों के सामूहिक प्रयासों और प्रगति को कमज़ोर करेगा। एक चौथाई से अधिक लोगों ने कहा कि उनकी गतिविधियों की पुन: योजना, और दाताओं के साथ समन्वय और संचार में उनका अधिकांश समय जा रहा है।***

*मुख्य सुझाव (नागरिक समाज नेतृत्व द्वारा प्रस्तावित):*

* **दाता संगठनों (फंडिंग ऑर्गनाईज़ेशन) लिए** 
  + ***संगठनों द्वारा वर्तमान में सामना की जा रही अभूतपूर्व चुनौतियों के कारण समय सीमा, रिपोर्टिंग मानकों और डाटा की आवश्यकताओं में अधिक लचीलापन प्रदान किया जाए***
  + ***संगठनों को विश्वास दिलवाया जाए कि समाज के अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाएगा***
* ***विभिन्न स्तरों पर सरकारों के लिए***
  + *छोटी भौगोलिक क्षेत्रों (जैसे शहरी क्षेत्रों में वार्ड या ज़ोन) के प्रबंधन के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं जैसे स्थानीय सरकारों और सामुदायिक संगठनों को शामिल करना*
  + *पीडीएस के सार्वभौमीकरण के माध्यम से प्रभावितों (विशेषकर प्रवासियों और दैनिक यात्रियों) को वित्तीय और भोजन संबंधी सहायता प्रदान करना, छोटे व्यापारियों और किसानों को वित्तीय राहत देना*
  + *ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा (MNREGA) के माध्यम से तत्काल रोज़गार उपलब्ध कराना*
  + *सरकार को लॉकडाउन की योजना बनाने से पहले स्थानीय हितधारकों जैसे कि नागरिक समाज संगठनों और यूनियनों से परामर्श, और सूचनाओं और नियमों को आसानी से उपलब्ध और सुलभ बनाना*

1. इस रिपोर्ट को प्रोफेसर अंकुर सरीन ने आईआईएम अहमदाबाद से जुड़े शोधकर्ताओं की एक टीम- बियांका शाह, ईशु गुप्ता, करण सिंघल और श्रद्धा उपाध्याय के साथ मिलकर तैयार किया है। डेटा विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन में सहायता के लिए वे प्रियंका साहू के आभारी हैं। वे नागरिक समाज संगठनों के 65 से अधिक नेताओं का अपना समय देने लिए और इस अध्ययन को सूचित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं और प्रोफ़ेसर मधुकर शुक्ला और प्रोफेसर एम.एस. श्रीराम का अपने अत्यंत मूल्यवान सुझावों के लिए। [↑](#footnote-ref-1)